दूसरी बात यह है कि सरस्वती जहाज जो डूब गया था उसकी रिपोर्ट क्या है। वह मिला या नहीं?

†شری محمد امین : مہودے میرے دو سوال ہیں جن کا جواب میں مانیہ منتری جی سے چاہوں گا ایک تو یہ کہ جو ٹکنٹ سے ۳۰ پرسینٹ آدمیوں کے رکروٹمنٹ کا فیصلہ ہوا تھا اس پر عمل درآمد ہوا یا نہیں اگر ہوا ہے تو کتنا ہوا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ سرسوتی جہاز جو ڈوب گیا اس کی رپورٹ کیا ہے وہ ملا یا نہیں۔

श्री जगदीश टाइटलर : हमारी नालेज में कोई सरस्वती जहाज डूबा नहीं । आपके पास इंफोर्मेशन है तो आप बता दीजिए हम पता लगाएंगे। जहां तक रेक्रूटमेंट का मामला है हमारे पास कन्सेंट आई हुई है। हम इस पर ध्यान दे रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : I shall now put the motion to vote. The question is :

"That the Bill further to amend the Merchant Shipping Act, 1958, be taken into consideration."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE CHAIRMAN : We shall now take up clause by clause considertion of the Bill.

Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI JAGISH TYTLER : Sir I move :

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

I STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE KALAKSHETRA FOUNDATION ORDINANCE PROMULGATED BY PRESIDENT ON 29TH SEPTEMBER, 1993

II THE KALAKSHETRA FOUNDATION BILL, 1993

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं संकल्प उपस्थित करता हूं कि--

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 29 सितंबर, 1993 को प्रख्यापित कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान अध्यादेश, 1993 (1993 का सं० 31) का निरनुमोदन करती है ।"

महोदय, वर्तमान विधेयक के संबंध में भारत सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति जी ने 29 सितंबर, 1993 को एक अध्यादेश जारी किया : मान्यवर, अध्यादेश के जरिए कानून बनाना यह कोई अच्छा परिपाटी नहीं है और इसके संबंध में संविधान में भी व्यवस्था दी गई है । उस में यह व्यवस्था दी गई है कि उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिन के कारण तुरन्त कार्यवाही करना उनके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेंगे । तो मान्यवर, आप देखेंगे कि भारत सरकार को देखना चाहिए था कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं जिन के कारण तुरन्त अध्यादेश के जरिए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी । मान्यवर, मैं समझता हूं कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी, न कोई ऐसी आवश्यकता थी और न कोई औचित्य था । मेरी समझ में ऐसी कोई परिस्थिति विद्यमान नहीं थी कि सरकार को वर्तमान विधेयक के संबंध में 29 सितंबर, 1993 को अध्यादेश जारी करना पड़ा । संसद का सत्र एक-डेढ़ महीने के बाद होना था । तो संसद की उपेक्षा करके अध्यादेश द्वारा कानून बनाना अच्छी परिपाटी

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

नहीं है। इस संबंध में पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष बराबर यह व्यवस्था देते रहे हैं और उन्होंने इस बारे में नियम दिए हैं—

> "The procedure of the promulgation of Ordinance is an inherently undemocratic one."

मावलंकर साहब ने यह व्यवस्था दी थी—it is desirable to restrict the use of Ordinance making power. इसलिए जो यह विधेयक है इसके प्रावधानों के संबंध में बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन जो पिछला सत्र समाप्त हुआ और वर्तमान सत्र शुरू हुआ, जहां तक मुझे स्मरण आता है करीब-करीब 7 अध्यादेश इस बीच में जारी किए गए हैं। उनमें से यह वर्तमान अध्यादेश भी एक है। कम से कम मंत्री जी जब अपना उत्तर देंगी तब जरूर इस चीज को बताने की कृपा करेंगी कि कौन सी ऐसी आवश्यकता थी, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं जिनके कारण सरकार को यह अध्यादेश लाना पड़ा।

इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में इस बात को बताया गया है कि यह एक कलाक्षेत्र मद्रास, जो प्रस्तुतीकरण कला के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की प्रख्यात संस्था हो गई है और प्रारंभ में उसके संस्थापक स्वर्गीय रुक्मणी देवी रही हैं। यह न केवल संस्थापक थीं बल्कि स्वयं एक विचारक और शिक्षाविद् भी थीं। यह निर्विवाद है यह संस्था बहुत ही अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और इस विधेयक के जरिए इस बात को लाने की कोशिश की गई है, संस्थापक के आदर्शों को जीवित रखना, कला क्षेत्र द्वारा स्थापित शृंखला के मानदंड की निरंतरता और कला और ललित कलाओं के भिन्न रूपों में श्रेष्टता बनी रहना, संस्था को उसके भविष्य के कियाकलापों को सुनिश्चित करने के लिए, सुदृढ़ नींव पर रखा जाना। इसमें यह भी कहा गया है कि जो इसके कर्मचारी थे वे बराबर इस बात की मांग कर रहे थे क्योंकि उनको उचित वेतन नहीं मिल रहा था, उनकी हालत जीर्ण-शीर्ण हो रही थी। इसी कारण से यह विधेयक लाना पड़ा। इसमें एक बात की और चर्चा की गई है कि संकाय के सदस्यों और कर्मचारिवृंद के वेतन भी केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम थे। बहुत से भवनों को तुरंत नवीकरण की आवश्यकता थी। उपस्करों और अन्य आवास रचनाओं की अति कमी हो गई। लेकिन सम्पूर्ण विधेयक में इस बात की कहीं चर्चा नहीं की गई है जैसा कि धारा 20 में कहा गया है वहां के जो कर्मकारी हैं वे इन प्रतिष्ठान के कर्मचारी हो जाएंगे लेकिन कर्मचारियों के वेतन में कोई वृद्धि होगी या नहीं, भत्तों में कोई वृद्धि होगी या नहीं, राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वे केन्द्रीय सरकार के समान होंगे या नहीं ? इस बात का कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि इस सिलसिले में मंत्री जी को विधेयक प्रस्तुत करते समय निश्चित रूप से आश्वासन देना चाहिए कि वहां के जो कर्मचारी हैं जिनके बारे में उद्देश्यों और कारणों में चर्चा है उनका वेतन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष होगा या नहीं।

दूसरे इसमें चार-पांच और चीजों की व्यवस्था की गई है। धारा 15 में विद्या समिति की चर्चा की गई है। धारा 11 में शासी बोर्ड की चर्चा की गई है। धारा 17 में वित्त समिति की चर्चा की गई है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि शासी बोर्ड या गवर्निंग बाडी में 12 सदस्य होंगे। इसके अलावा इसमें एक चेयरमैन होगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें आपने बहुत से लोगों की चर्चा की है इसमें कम से कम संसद सदस्यों में से भी प्रतिनिधि होना चाहिए। धारा 11 में आपने कहा है कि शासी बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। इसमें एक अध्यक्ष होगा जिसे केन्द्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। दूसरे जो बारह सदस्य होंगे वे केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्तियों में से नामनिर्देशित करेगी जिन्होंने कला क्षेत्र की बहुमूल्य सेवा की है, जो कला, संस्कृति, लोक कला और शिल्प कला से संबद्ध रहे हैं, जो ख्याति प्राप्त

कलाकार हैं और जो कला और संस्कृति के आश्रय-दाता हैं और दो व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके पास खंड (ख) के उपखंड (1) से उपखंड (4) में निर्दिष्ट एक या अधिक अर्हताएं हैं, राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित किया जाएगा । मेरा इसमें यह भी कहना है कि इसमें संसद का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए ।

इसके अलावा में एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इस विधेयक के द्वारा जो अच्छा काम किया है उसका मैं स्वागत करता हूं कि जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था है उसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने जा रहे हैं इस विधेयक के जरिये । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का निरनुमोदन करता हूं ।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to move :

"That the Bill to declare Kalakshetra of Madras to be an institution of national importance to provide for the estiblishment and incorporation of a Foundation for its administration, to make provisions for further development of Kalakshetra in accordance with the aims and objects for which Kalakshetra was founded and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

Sir, Kalakshetra, Madras, is an internationally renowned cultural institution established by late Smt. Rukmani Devi Arundale in 1936. The main objects of the Kalakshetra are to emphasise the essential unity of all true arts, to work for the recognition of the arts as vital to individual, national, religious and international growth, and to maintain the highest traditions of art and culture in their pristine purity, to conform to our traditions and to arrange for the training, research, study, teaching and development of art and science, music, Bhartanatyam dance, drama etc. and other fine arts in conformity thereto.

These aims and objectives were pursued by the founder Direcetor and her followers with great vigour and today Kalakshetra has earned for itself an international status and recongnition because of the exellence of the training it has given to its students and other activities.

This great institution suffered a setback in the year 1987 on the death of its founder Smt. Rukmani Devi Arundale. Thereafter, the institution was beset with lots of financial, managerial and other administrative problems. There was also pressure from vested interests to take over the institution. There has been litigation between the Society and the Trust. These problems threatened the very existence of such a great institution. To add to these problems, a brutal attack on the surviving trustees took place recently. There was also a clear threat of usucaption of the property of the Kalakshetra. It is in this context, the Government felt the imperative necessity for taking immediate action. As the authorities of the Kalakshetra, Madras, themselves requested the Government in the year 1991-92 to declare it and its constituent units as an institution of national importances and having regard to the urgency, it was decided to promulgate an ordinance to declare the great institution as an institution of national importance and to provide for its management and finances.

Therefore, in this context, I move that the House may kindly consider and pass the Bill which seeks to replace the Ordinance.

The questions were proposed.

SHRI VISHVJIT P. SINGH (Maharashtra) : Mr. Vice-Chairman, Sir, we often, in this House and outside this House tend to get taken up by the sweep of events, politics personal pre-occupations, and other petty matters of everyday life. In the ultimate analysis, Mr. Vice-Chairman, Sir, these are but petty matters. What really matters, what is of real importance in our lives, we tend to lose sight of. More so

with the growth of our population, with the growth of our cities, our priorities change over a period of time. I find, Sir that in these few years that I have been in this House, it is not very often that we pay attention to that which feeds our minds our culture, and our civilization. We allocate our scarce resources with great care. We husband our money and spend it—at least, try to spend it—wisely. In this whole process, very little is left over for that essential which we have lost sight of; our culture, education, civilisation. Therefore, on rare occasions when this House is called upon to allocate funds and take care of the minds of our people, I see those rare occasions as occasions of pride for us. There is a sense of satisfaction in doing this. There is a sense of pride, as I said. That is why I welcome this legislation.

The repositories of our culture, we tend to ignore, we tend to forget them; whether it is our museums, whether it is our libraries, whether it is the various craft centres. We tend to forget them. Of course, occasionally, attention is paid to them when festivals are organised, when functions are organised. For example, when we retire from Parliament, a huge cultural show is organised for us. Once in two years, a cultural show is organised for the retiring Members. We see it and then we tend to forget it.

Sir, ours is a very ancient tradition. It is not only an ancient tradition. It is a unique tradition becausing it is unbroken. Our culture has an unbroken lineage stretching to thousands of years. India has been the melting pot of the cultures of the whole region; whether the culture came from Iran, whether it came from Arabia, whether it came from China, whether it came from Tibet, it came to India and got amalgamated into the great Indian culture.

This institution which we are talking about today was in the forefront of the revivalist movement. When we, as a nation, woke up, when we became alive to our culture, certain individuals established institutions throughout the country at that point of time which led to the resurgence of the Indian culture which we see today.

The late Shrimati Rukmini Devi, a person of international fame, represented within herself all that was finest in the Indian tradition. She was a great *sishya* first and was a great *guru later*. She learnt at the feet of great masters and she became one herself. She imparted knowledge to many generations. She made the world aware of what India had to offer. She was one of the first persons who acted as a medium to carry the message of the Indian musical tradition and the Indian dance tradition to Europe, America and other parts of the world.

Mr. Vice-Chairman, as I said before, our institutions are the repositories of our culture and the Kalakshetra institution in Madras with its various units was one such repository of our culture. I deliberately use the word 'was' because institutions are built up by individuals and the individual in this particular case was larger than life Shrimati Rukmini Devi Arundale. She faced the same vicissitudes which are faced by all those who seek to build up institutions in the face of an indifferent or hostile environment. We must not forget, Mr. Vice-Chairman, we live in Kalyug. In this Kalyug, as I said before, we have no time for our culutre, we have no respect for it, we pay lip service to it but in real terms very little is done. For that same great institution of Kalakshetra adequate funds were not forthcoming. Even during the lifetime of Shrimati Arundale funds were not forthcoming. She found herself at a loss. It was purely the strength of her personality that kept the faculty together. The entire faculty of individuals here was committed to India, to Bhart as a nation, to the concept of our culture. The commitment of the entire faculty and Shrimati Rukmini Devi was such that salaries did not matter to them, comforts did not matter to them. They imparted their message regardless of the vicissitudes which they faced.

Unfortunately, as the hon. Minister has said just now, that institution which was

founded in 1936 finally reached its nadir in 1987 with the death of the founder. Fifty-one years, half a century, after its foundation, with the death of the founder, you can imagine the situation. The faculty got demoralised with the moving spirit having gone for ever—the memory still lingers but the moving spirit is gone. The public is indifferent, nobody is doing anything about it, yet the faculty persevered, carried on and carried on and said, "Yes, we will keep the institution alive." The staff worked at lower salaries, even worked for no salaries and then came the shock. This is a cruel world, Mr. Vice-Chairman. That cruelty was beyond comparison. The greed of individuals cannot be measured. They fell upon the institution like carrion coming for a picking on a dead body. No sooner had Madam Arundale departed from this earth, than those assets of Kalakshetra which she had assiduously built up over the years, which she had cultivated over the years, become its greatest enemy.

5.00 P.M.

Hungry eyes looked upon those assets. Evil minds planned to take them over. Those evil intentions came to the fore in the form, first, of threats, which were not listened to, then, through litigation. We all know our legal system. We all know how certain clever individuals can, for a certian time, take advantage of the legal system and derive certain temporary advantages from it. Stay orders were sought from the courts. All kinds of litigation went on. The idea was to browbeat the trustees into submission. When even that failed, the final part of the plan unfolded and actual physical attacks took place upon the faculty members of the Kalakshetra institution. And all this while the Government was being petitioned—the State Government. And then the Central Government. It was being petitioned by the Kalakshetra institution, by the faculty, by the society, "Kindly do something about it; various members who feel for it want something to be done." To the credit of the hon. Minister, something is finally done. It is done only after physical attacks had taken place. That's why I would like to point out—Mr. Malaviya is no longer present in the House—that the fact is, the Government was forced into promulgating the Ordinance because physical attacks had actually started. It was a time to put a stop to it. Waiting for Parliament to reconvene would probably have given them more leeway. To stop this—the nefarious designs of those who wanted to take over this institution, those who wanted to suborn this institution to their own benefit, the property developers and people who wanted to take over the institution—this was done and they were stopped by this Ordinance.

I will now come, Mr. Vice-Chairman, to the Bill itself. The Bill, though it short, is an all-encompassing Bill. The objects are clearly laid down. The objects, let me remind you, Sir, are the same as enunciated by Shrimati Rukmini Devi Arundale for Kalakshetra. There is no change in the objects. Government has not changed the objects. The objects remain the same which were the objects of Kalakshetra when it was founded in 1936 :

(1) To emphasize the essential unity of all true arts ;

(2) to work for the recongnition of the arts vital to the individual, national and international growth ;

(3) to maintain the highest traditions of art and culture in pristine purity and in conformity with traditions ;

(4) to arrange for the training, research, study, teching and development of art and science, music dance drama, fine arts, Bharata Natyam ; and

(5) to ensure that the principle of education without fear and art without vulgarity ...

Unfortunately Mr. Baby has gone—and I wanted him to hear this :

"to ensure that the principle of education with fear and art without vulgarity are adhered to in the activities of the Foundation and not to permit any deviation from these high ideals."

These are the objects of the Foundation and the Foundation has been well-catered to by a three-layered body which has been set up—The Governing Board, the Academic Committee and the Finance Committee.

The Governing Body with 19 members ...

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA : Twelve.

SHRI VISHVJIT P. SINGH : Nineteen. I am coming to that. It is not twelve. There are nineteen members, It says :

"The Governing Board shall consist of—

"(a) a Chairperson ... appointed by the Central Government ;

"(b) ... twelve Members to be nominated by the Central Government from amongst persons who—

"(i) have rendered valuable service to Kalakshetra ;

"(ii) have been connected with, or have knowledge of art, culture, folk arts and crafts ;

"(iii) are eminent artistes ; and

"(iv) are patrons of art and culture ;"

These are the qualifications. Apart from them, two persons possessing these qualifications are to be nominated by the State Government, two officers of the Central Government, not below the rank of Deputy Secretary, to represent the Ministry of Central Government dealing with culture *ex officio*, one officer of the Central Government, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by that Government to represent the Department of Education, *ex officio* and lastly the Director.

It makes a total of 19 members.

Apart from this, there shall be an Academic Committee. It is the Academic Committee which shall be responsible. Section 16 clearly spells out what the Academic Committee will do. The most important element in this whole Scheme is the Academic Committee. It says :

"The Academic Committee shall be responsible for the maintenance of standards of education, training and examination conducted by the constituent units and shall exercise such other powers and perform such other functions as may be assigned to it, from time to time, by the Governing Board."

This is going to look after the day-to-day functioning of the Foundation. The Governing Board will meet twice a year. That is purely an overseeing body. It is the Academic Committee which shall be really responsible. It says :

"The Academic Committee shall consist of—

"(a) Director ;

"(b) the Heads of the constituent units :

"(c) three distinguished persons in the field of art and culture including dance, music, folk arts and crafts, to be nominated by the Central Government ; and

"(d) one person to be nominated by the State Government, representing the Department of Education of that Government."

Both the Central Government and the State Government have been adequately looked after in both these bodies.

Finally, Mr. Vice-Chairman, what is the Finance Committee going to do ? Section 18 says :

"(i) scrutinise the annual statement of accounts and budget estimates of the Foundation prepared by the Director and make recommendations to the Governing Board ;

"(ii) presiribe the limits of the recurring and non-recurring expenditure of the Foundation for each financial year ;

"(iii) review the financial position of the Foundation from time to time and have an internal audit conducted ; and

"(iv) perform such other functions as may be prescribed."

Section 17 says :

"The Finance Committee shall consist of—

"(a) the Financial Adviser to the Government of India or his niminee in the Ministry of the Central Government dealing with culture ;

"(b) an officer of the Central Government, not below the rank of a Deputy Secretary, to be nominated by that Government ;

"(c) an officer of the State Government not below the rank of a Deputy Secretary, to be nominated by that Government, representing the department of Finance of that Government ; and"

once again :

"(d) the Director."

The Director is a member of all the bodies.

Also specified, as I said before, is who can be a member. The qualifications have been very clearly given.

The Finance Committee shall produce its report, and like any other institution run by the Government of India it shall get grants from the Government, which will be voted by Parliament. Section 21 says :

"For the purpose of enabling the Foundation to discharge its functions efficiently under this Act, the Central Government, may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, pay to the Foundation in each financial year, such sums of money, on such terms and conditions as that Government may determine, by way of grant, loan or otherwise."

Also, the Foundation will have its own Fund, its own cropus, which shall be built up, which shall be contributed to both by the State Government and by the Central Government and by anybody else who wishes to because there will be some tax exemptions, and that will become the corpus of this Foundation.

Not only that, but, Mr. Vice-Chairman, it shall be subject to audit by the Comptroller and Auditor-General of India. Furthermore, a report shall be prepared. The accounts shall be forwarded to the Central Government and shall be laid before each House of Parliament. This is a comprehensive Bill.

After saying all this, I have one last point to make. I have only one apprehension. I have to voice this apprehension to the hon. Minister. Norms have been prescribed for the qualifications and for the appointment for practially everbody, for members and even the faculty, but unfortunately no norms have been prescribed for the Director. That is an oversight, which I would like through your medium to point out to the Hon. Minister. I am sure it does not need to be put into the Act, but due caution should be taken. I am sure the Minister will give such an assurance, because if you see Section 19—Appointment and duties of Director, it merely says in sub-section (1) :

"The Central Government shall by notification appoint a Director, who shall be the principle executive officer of the Foundation and who shall be responsible for the proper administration of the affairs of the Foundation and its day-to-day management and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be asigned to him by the Governing Board.

(2) The Director shall prepare the annual statement of accounts and budget estimates of the Foundation for scrutiny by the Finance Committee.

(3) The Director shall be a whole-time employee of the foundation and shall be entitled to such salary and allowances out of the Fund and shall be subject to such conditions of service in respect of leave, pension, provident fund and other matters as may be prescribed."

Unfortunately even the earlier section which deals with Director and which talks of the Governing Board, where it gives qualifications of 12 Members and then goes to talk about two other persons to be nominated by the Central Government and says they will also have to have the same qualifications as those of 12 Members. Other officers are to go there as ex-officio officers, but there is no qualification given for the Director. I would like to know from the hon. Minister if this is a deliberate oversight or there is some reason for this. In any case, I am sure, the hon. Minister will give us an assurance that she will make sure that the Director does have certain minimum qualifications, and she will disclose to the House what those minimum qualifications would be.

I have only one more request to make to the hon. Minister. There are various other institutions in this country. There are libraries. Even in my district, Sitapur, there is a library belonging to the Raja of Mahmudabad. Though the Raja tries to pay as much as he can towards its maintenance, that is still not enough and many of the books are falling into disrepair. My own grand-father's library my father presented to the University. So, I do not have any such problem. But there are various other libraries in different parts of the country and other institutions in various parts of the country. For example, there is a museum of Indian musical instruments in the Rampur Palace, which is probably a unique museum in the world. It has the largest collection of Indian musical instruments from all over India, including the tribal areas. The whole set-up is under a tremendous amount of litigation, especially after the death of the Nawab and of Mikimian, Zulfikar Ali Khan, who was a member of the Lok Sabha. Unfortunately, there is a tremedous amount of litigation. Even the wood of the musical instruments is not oiled and they are falling apart. Its windows are broken. It is open to the weather. I would be very grateful if you unilaterally do something in this case. You can unilaterally ask your Department to conduct a survey of those institutions of cultural importance which are falling into disrepute. Kindly do something about them and take them over. The money which is involved, though may seem a lot to us, is actually minimal. The benefits which will accrue from this action will be tremedous.

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक हमारे सामने पेश हुआ, यह आर्डिनेंस 31 को रिपील करके विधेयक बनाने के लिए लाया गया है। विधेयक के उद्देश्य और कारणों में जिन बातों को कहा गया है, वह बहुत ही प्रशंसनीय हैं। यह संस्था कला क्षेत्र की हमारे देश की एक मूर्धन्य कलाकार, डांसर, रुकमणी देवी अरूंडेल के द्वारा बनी हुई है, उसके द्वारा स्थापित हुई है। मेरे से पूर्व वक्ता ने सही कहा कि बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने इस संस्था को वहां खोला था। यूं तो महोदय देखा जाए तो जो भी संस्था कोई एक व्यक्ति शुरू करता है तो उसे बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और हम देखें तो हमारी आजादी के संघर्ष के दौरान हमारे देश में कई जगहों में कला और संस्कृति के विकास के लिए कुछ लोगों ने बहुत प्रयास किए। आप अगर देखेंगे तो बंगाल में गुरु रविन्द्र नाथ ठाकुर ने शांति निकेतन की स्थापना की और उसका उन्होंने विकास किया। पूर्वांचल की कला, संस्कृति, नृत्य, गीत आदि का उन्होंने विकास किया। दक्षिण में रुकमणि देवी ने उसी प्रकार से कला क्षेत्र का विकास किया, उसकी स्थापना की, उसको बढ़ाया और जो नृत्य हम समझते थे, हमारे देश की यह मान्यता थी कि मंदिरों में देवदासियां वह नृत्य करती हैं, "भरत नाट्यम" के नृत्य को एक ऊंचा दर्जा दिया और ऊंचाई तक पहुंचाया। सारे विश्व में "भरत नाट्यम" आज एक ऊंचे दर्जे की नृत्य-कला है। ठीक है, रुकमणी देवी के जाने के बाद इस संस्था की कोई देखभाल करने वाला नहीं था। यह टूटने लगी और जैसे हम जानते है कि कहीं पर कोई सम्पत्ति हो तो लोग खड़े हो जाते हैं दखलंदाजी के लिए तो वहां भी यह झगड़ा-चला और सरकार को बाध्य होकर एक आर्डिनेंस जारी करना पड़ा और फिर यह विधेयक

लाया गया । विधेयक के बारे में जो बातें कही गई है, मैं उन्हे दोहराना नहीं चाहती, बहुत लम्बी तफसील के साथ हमारे पूर्ववक्ता ने इसमें से उद्धरण के साथ बातों को कहा । मैं केवल कुछ दो-चार बातें आपके सामने, सरकार के ख्याल के लिए रखना चाहूंगी । एक तो आप अगर देखें, कला क्षेत्र फाउंडेशन चैप्टर 3 में :—

"9. The objects of the Foundation shall be,—

(i) to emphasise the essential unity of all true arts ;

(ii) to work for the recongnition of the arts as vital to the individual, national and international growth ;

(iii) to maintain the highest traditions of art and culture in their pristine purity and in conformity with traditions ;

(iv) to arrange for the training, research, study teaching ... fine arts and Bhart-Natyam ;"

मैं इसमें कहना चाहूंगी, महोदय, कि चैप्टर 3 के क्लाज नम्बर 9 की सब-क्लाज 4, जिसको मैं पढ़ रही थी अभी, इसमें मंत्री महोदया को भरत नाट्यम के अंत में जोड़ना चाहिए कॉमा के, एण्ड को डिलीट करके, इंडियन क्लासिकल डांसिस । केवल भरत नाट्यम ही एक ऐसा नृत्य नहीं है जो भारत का प्रसिद्ध नृत्य हो । जो अन्य दक्षिण क्लासिकल डांसेज हैं—कुचि पुड़ी, कथा कली, उनको भी जोड़ना चाहिए । उड़ीसी भी है, उत्तर भारत के भी कुछ उसमें नृत्य कला को जोड़ा जा सकता है । इसमें जो फॉक डांस के बारे में भी कहा गया, फॉक आर्ट के बारे में कहा गया, तो हमारे देश के दक्षिण भारत और उत्तर भारत के जो फॉक डांसेज हैं, उनको भी इसमें जोड़ना चाहिए था । महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि इसमें आर्ट ऑफ साईस है । अब आर्ट एंड साईस को एक साथ जोड़कर आप बात कर रही हैं मंत्री महोदया । मुझे समझ नहीं आता है कि उनके बारे में आपके मानस क्या हैं ? आप अगर साईस एण्ड आर्ट कहती तो बात समझ में आती । कला की जो वैज्ञानिक दृष्टि है उसके बारे में भी यह बात कही जाएगी । लेकिन विज्ञान तो अलग ही अगाध समुद्र है, उसका अलग क्षेत्र है । तो कला के साथ विज्ञान को जोड़कर क्या आप उसमें कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला वगैरह खोलना चाहती हैं, इसको स्पष्ट करना चाहिए, नहीं तो फिर यह साईस शब्द को हटा देना चाहिए । क्योंकि मेरे ख्याल से अगर इसमें साईस शब्द को रखेंगे तो यह साईस के साथ मजाक करना होगा । इसके बाद उन्होने कहा कि :

"to ensure that the principles of "education without fear" and "art without vulgarity" are adhered to in the activities of the Foundation and not to permit any deviation from these high ideals."

यह बहुत ही अच्छी बात है । अगर सरकार को कला क्षेत्र फाउंडेशन के लिए यह उद्देश्य हो सकता है तो हमारे देश के कला संस्कृति के लिए क्यों नहीं यह उद्देश्य हो सकता है ? महोदय, अगर आप आज हमारे देश में देखें तो आर्ट एंड कल्चर की जो वल्गारिटी चरम सीमा पर पहुंची है और सरकार चुप है । जो सबसे आसान मीडिया है—सिनेमा और टेलीविजन के द्वारा जी० टी० वी० आदि द्वारा दिखाया जा रहा है और क्या-क्या नहीं दिखाया जा रहा है । इसके जरिए हमारे पूरे यंगर जेनिरेशन को वल्गराइज किया जा रहा है । तो केवल एक फाउंडेशन के जरिए, कलाक्षेत्र फाउंडेशन का जब हम कानून बना रहे हैं... (व्यवधान) मंत्री महोदया, अगर आप सुनती तो बड़ी कृपा होती।

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : I would request the Minister to kindly pay attention to the Speaker.

श्रीमती कमला सिन्हा : मैं यह कह रही थी कि कलाक्षेत्र फाउंडेशन बनाने के लिए अपने विधेयक के चैप्टर-3 में यह रख दिया कि :

"to ensure that the principles of "education without fear" and "art without vulgarity" ..."

तो मैं यह कह रही थी कि इस फाउंडेशन में आर्ट विदाउट वल्गारिटी हो, लेकिन हमारे देश में आर्ट विद वल्गारिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सरकार की उधर कोई दृष्टि ही नहीं है। हमारे मीडिया में, टेलीविजन में जो दिखाया जाता है वह आर्ट नहीं कहा जाता, सीधे-सीधे उसको वल्गार आर्ट कहना चाहिए। तो क्या सरकार उसको रोकेगी ? वह जो माइकल जेक्शन हमारे यहां आने वाले थे तथा आते-आते रुक गए, तो हमारे पूरे यंगर जेनिरेशन को तथा मंत्री महोदया भी खुद बहुत यंग हैं, पता नहीं वे माइकल जेक्शन की फेन हैं या नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन यह पूरे यंगर जेनिरेशन को खराब करने का, वल्गार करने का यह तरीका अपनाया जा रहा है। तो एक तरफ कलाक्षेत्र के फाउंडेशन बनाते समय ऊंची-ऊंची बड़ी बात कही जाए और दूसरी तरफ पूरे देश में कला संस्कृति और हमारे मीडिया के जरिए गिरी हुई चीज दिखाई जाए जिससे पूरे नेशन को बरबाद किया जाए, आने वाली पीढ़ी को बरबाद किया जाए, तो यह नहीं होना चाहिए। केवल एक सीमित क्षेत्र में बड़ी बात कहना और असीम क्षेत्र में पूरे देश के पैमाने पर वल्गराइज कराना, यह दो तरह की बात होती है। सरकार को दो तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो महोदय, मैं आपके सामने इस बात को उठाना चाहती थी। दूसरी बात यह कि इसकी जो कमेटी होगी उसके बारे में कहा गया कि कौन-कौन लोग होंगे, कैसे इसका काम चलेगा, वह सब इसमें है। एक जगह तो कहा गया कि डॉयरेक्टर एक्स-औफिशियो होंगे। यह मेज नंबर 6 में है। चैप्टर 3 में क्लाज नंबर 2 में कहा गया है कि——

Governing Body shall consist of such and such persons.

उसमें चेयरमैन है, कमेटी के कौन-कौन मेंबर होंगे, कैसे-कैसे होंगे, एमीनेंट परसन, एमीनेंट आर्टिस्ट, आर्ट और कल्चर आदि-आदि दिया गया है। इसमें उन्होंने कहा कि डॉयरेक्टर, एक्स-औफिशियो होंगे। दूसरी तरफ पीछे इन्होंने पेज नंबर 8 में कहा है कि——

"Director shall be a whole-time employee of the foundation."

तो एक तरफ एक्स-औफिशियो होगा और दूसरी तरफ——

"Director will be the key person."

तो इस डॉयरेक्टर की बहाली का क्या क्राईटीरिया होगा क्योंकि——

He will be the key person, the kingpin for this foundation.

तो डॉरेक्टर की बहाली का क्या प्रिंसिपल होगा? अभी जो डॉरेक्टर काम कर रहे हैं कला क्षेत्र में, उन्हीं को बनाया जाएगा या दूसरी क्या खोजना है, यह विधेयक में साफ-साफ कहना चाहिए था नहीं तो संदेह पैदा होता है।

मैं इतनी बात कहने के बाद अंत में यह कहना चाहूंगी कि हमारे देश में सरकार ने फाउंडेशन तो बहुत बनाए, विधेयक भी बहुत बनाए और कला और संस्कृति के क्षेत्र को अपने हाथ में लिया। अभी शांति निकेतन का नाम मैंने लिया, विश्व भारती का नाम मैंने लिया। विश्व भारती भी आज दुर्दशा की स्थिति से गुजर रही है, उपेक्षा की स्थिति से गुजर रही है। उसी तरह अनेकों संस्थाएं में गिना सकती हूं। रुक्मिणी अरुंडेल तो वैसे प्रशंसा के लायक हैं, हमारा सिर उनके सामने झुकता है लेकिन उनके द्वारा स्थापित यह संस्था सही मायनों में काम कर सके आने वाले दिनों में, यह देखना चाहिए। जिन उद्देश्यों को लेकर आप यह विधेयक लाए हैं, वह सही मायनों में पूरा हो सकेगा, क्या सरकार इसकी गारंटी देगी ?

दिल्ली में ही देखिए, दूर नहीं जाना पड़ेगा, मंडी हाउस में तरह-तरह की संस्थाओं को जगह दे रखी है और वहां व्यापार हो रहा है कला के नाम पर। तो क्या इस तरह का कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर उसके लिए होगा, कोई सेफ्टी वॉल्व होगा कला क्षेत्र के लिए ? वह होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम सरकार की क्या मंशा है लेकिन कला क्षेत्र के लिए एक सेफ्टी वॉल्व होना चाहिए ताकि ये संस्थाएं आगे चलकर बेकार न हो जाएं।

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Hon. Member, at 5.30 there is a statement to be made by the Finance Minister. May I request you to conclude within two or three minutes ?

SHRIMATI KAMLA SINHA : Yes, I am concluding.

मेरे पूर्व वक्ता ने अपने इलाके, अपने परिवार और अन्य इलाकों और अपने जिले के आसपास की लाईब्रेरी आदि के बारे में कहा। मैं बिहार की हूँ। मुझे याद आया, पटना जिले में एक गांव है भरतपुरा। वहां के जो जमींदार लोग थे उन्होंने अपने परिवार में एक लाइब्रेरी बनाई। मैंने देखा है उस लाईब्रेरी को। आज भी उसकी थोड़ी सी जमीन दे रखी है और देखभाल करने के लिए कुछ लोगों को रखा है लेकिन उस लाईब्रेरी में कुछ पुस्तकें और कुछ चित्र अमूल्य हैं और वह मूल प्रति है, सारे हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है। तो सरकार को पूरे देश में जहां कहीं इस तरह की चीजें हैं, उसका एक ब्योरा बनाना चाहिए। ब्योरा बनाकर उसकी सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए क्योंकि मैं जब गई थी भरतपुरा पिछले साल तो लोगों ने मुझ से कहा कि बहुत दिन हम ये बोझ उठा नहीं सकेंगे। आए दिन मूर्ति, पुस्तकें, चित्र आदि चोरी होते रहते हैं। हम नहीं जानते हम कब तक इनको बचा पाएंगे। हमारी यह अमूल्य निधि विदेश चली जाएगी, किसी के घर में चली जाएगी और विदेशी चोरबाजारियों के हाथ में जाएगी। तो सरकार को जरूर इस पर सचेतन होना चाहिए, अगर सचमुच में भारत को कला और संस्कृति की रक्षा करनी है नहीं तो फिर इसको कला तो आ ही रही है। अगर उसी को बढ़ावा देना है तो यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद।

STATEMENT BY MINISTER

Income-tax Exemption to National Backward Classes Finance and Development Corporation and Similar State Corporations

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : Sir,

The National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance and Development Corporation and the various State level Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporations enjoy exemption from income-tax under the provisions of section 10 (26B) of the Income-tax Act. There is no parallel provision in the Act exempting the income of similar bodies engaged in promoting the interests of backward classes.

The National Backward Classes Finance and Development Corporation has been set up as a wholly owned Government company for promoting the interests of members of Backward Classes. Some States have also set up similar corporations for the benefit of Backward Classes. Considering the importance of these corporations in promoting the interests of Backward Classes, I have pleasure in announcing the Government's decision to provide income-tax exemption on the income of these corporations. The income-tax exemption will apply from financial year 1992-93 i.e. assessment year 1993-94 and onwards.

Necessary amendment in this regard will be proposed through the next Finance Bill.